8B/HP/09/28/2020/FC

I/56430/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.0177-2658285,
फैक्स/Fax: 0177-2657517

दिनांक. .10.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(e-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय **Diversion of 9.60 ha of forest land in favour of High Court of Himachal Pradesh for the construction of Judicial Court Complex in Mandi, under the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Others/42429/2021).**

सन्दर्भः **Online proposal no- FP/HP/Others/42429/2019 submitted by State Govt on 06.06.2023.**

महोदया/महोदय,

Regional Empowered Committee की संतुति के पश्चात् उपरोक्त प्रस्ताव को मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन हेतु भेजा गया था, मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव से सम्बंधित सूचना मांगी गयी है ।अतः राज्य सरकार निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यबाही की जा सके :-

In the extant proposal corresponding to budget of Rs 20 crores, the proposed built up area (appr. 48738 sq mtr) that including buildings, roads, parking etc seems exceptionally high which clearly shows that the minimum requirement of the forest area has not been proposed.

In addition, the certificate of minimum use of forest as signed by UA and DFO (at SN 20 of Additional documents of Part I of PARIVESH) talks about only the minimum no. of storeys that can be built (4 storeys only in the proposal) and doesn't talk about minimum forest area required.

Accordingly, State Govt is requested again to revisit the proposal and plan the project in such a way that minimum forest land will be used and then submit the revised proposal with a fresh certificate of minimum use of forest from DFO.

यहि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय,
ह ०/-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

Signed by Raja Ram Singh
Date: 29-10-2023 17:32:31
Reason: Approved

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).

2. वन मण्डल अधिकारी, मंडी वन मण्डल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivman-hp@hp.gov.in)

I/56430/2023

3. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (E-mail : dj.hp.mnd@gmail.com)